मूल्य 1 रु.
वर्षः 13 - अंक : 253, मुंबई, बुधवार, 29 नवंबर, 2023 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक
मुंबई हलचल
भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®
अब हर सच होगा उजागर

मध्य रेल आरपीएफ ने बचाई गई 66 जिंदगियां

2.77 करोड़ रुपये का सामान भी किया बरामद

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। मुंबई रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान यात्रियों एवं उनके बहुमूल्य सामानों की रक्षा में सदैव सबसे आगे रहते हैं। वे न केवल रेलवे संपत्तियों की चौबीसों घंटे निगरानी करते हैं, बल्कि घर से भागे बच्चों को बचाने वाले और सामान वापस लाने वालों की कई भूमिकाएं भी निभाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान मध्य रेल आरपीएफ कर्मियों ने मिशन जीवन रक्षक के तहत अपनी जान जोखिम में डालकर 66 लोगों की जान बचाई है। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

मुंबई में मराठी साइन बोर्ड को लेकर सख्त हुई BMC

शुरू हुई दंडात्मक कार्रवाई

हर वार्ड में कार्रवाई के लिए टीमें तैयार

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड मराठी भाषा में लिखे होने चाहिए। इसके लिए आज से बीएमसी प्रशासन एक्शन शुरू किया। इसके लिए सभी 24 विभागों में टीमें गठित की गई हैं और टीमों का कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड मराठी भाषा में मोटे अक्षरों में नहीं लिखे होंगे उनके मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मराठी में साइन बोर्ड लगाने की दो महीने की मोहलत दी थी। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

ठाणे में दुकानों पर पोती कालिख

ठाणे में भी मनसे कार्यकर्ताओं ने तीखे तेवर दिखाए। मनसे कार्यकर्ताओं ने उन शोरूमों पर कालिख पोत दी, जहां मराठी बोर्ड नहीं लगे हैं। मनसे ने ठाणे में दुकानों के साइन बोर्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। एमजी मोटर्स शोरूम को मनसे ने मराठी में बोर्ड लगाने की चेतावनी दी है। मनसे वर्ष 2006 से मराठी बोर्ड को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मनसे का आरोप है कि कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कुछ जगहों पर मराठी भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं।

मनपा अधिकारी जोशी व काबरे के मार्गदर्शन में टीमें गठित

अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी और उपायुक्त (विशेष) संजोग काबरे के मार्गदर्शन में कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। सभी 24 वार्डों के सहायक आयुक्तों की देखरेख में टीमें कार्रवाई करेंगी। जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों के बोर्ड मराठी भाषा में मोटे अक्षरों में नहीं लगाए गए हैं, उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वसूला जाएगा 2 हजार का जुर्माना

मुंबई में 5.5 से 6 लाख दुकानदार हैं। कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में बीएमसी प्रतिदिन के हिसाब से दुकानदारों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। बीएमसी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूल सकती है।

सोशल मीडिया से मिली जानकारी जनहित याचिका की दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिये एकत्र की गई जानकारी जनहित याचिका (पीआईएल) में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती। याचिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में हर साल असुरक्षित जल निकायों में सालाना डेढ़ से दो हजार लोगों की मौत हो जाती है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीड ने अधिवक्ता अजित सिंह घोरपड़े की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राज्य के जलप्रपातों और जल निकायों को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

चाचा भतीजा विवाद: एनसीपी हमारी है...

स्पीकर को अजित पवार का जवाब

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। चाचा भतीजे विवाद के बीच अजित पवार ने दावा किया है एनसीपी उनकी पार्टी है। संगठन से लेकर चुने हुए जन प्रतिनिधि तक, सब उनके साथ हैं इसलिए एनसीपी उनकी है। अजित दादा पवार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 260 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है। इसमें साफ तौर पर अजित पवार ने दावा किया है एनसीपी हमारी है। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

डिप्टी सीएम बनने के बाद अजित ने क्या कहा था?

डिप्टी सीएम बनने के बाद अजित पवार ने कहा था कि सभी विधायक उनके साथ हैं और वह शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास सारे आंकड़े हैं। सारे विधायक हमारे साथ हैं। हम एक पार्टी के तौर पर खुश हैं। लोकतंत्र में बहुमत को ही अहमियत दी जाती है। हमारी पार्टी 24 साल पुरानी है और ऐसे में अब युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

भेदभाव का नायाब नमूना

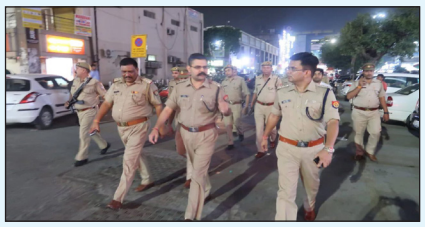

नोएडा में लड़कियां अब आठ बजे शाम के बाद क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। ऐसी रोक लगाते हुए इसे ध्यान में नहीं रखा गया है कि अनगिनत लड़कियां आर्थिक उपार्जन के लिए दिन भर कहीं काम करने के बाद शाम को क्लास ज्वाइन करती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने अपनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों/महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भरा कदम उठाया है। यह पुलिस का अपने दायित्व से मुकरना भी है और महिलाओं को घर के दायरे में धकेलने की उसकी सोच को भी जाहिर करता है। इस परियोजना के तहत कोचिंग एवं अन्य संस्थानों में शाम आठ बजे के बाद लड़कियों के लिए क्लास चलाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसी कोई रोक लड़कों पर लागू नहीं होगी। पुलिस की यह सोच घोर आपत्तिजनक है कि लड़कियों के सड़कों पर घूमने-फिरने से शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इस सोच में यह निहित है कि अगर लड़कियां घूमती-फिरती हैं तो यह पुरुष अपराधियों को जुर्म करने के लिए न्योता देने जैसा है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति भी है कि ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने में नोएडा पुलिस अपने को अक्षम मानती है। वह यह बात नहीं मानती कि सबको हर जगह सुरक्षित महसूस कराना उसका कर्त्तव्य है। पुलिस ने ऐसा निर्णय लेते वक्त इस हकीकत को ध्यान में नहीं रखा कि अनगिनत लड़कियां आर्थिक उपार्जन के लिए दिन भर कहीं काम करती हैं और करियर में आगे बढ़ने के लिए शाम की क्लास ज्वाइन करती हैं। बेशक राष्ट्रीय राजधानी के आसपास गुजरे वर्षों में महिलाओं के खिलाफ गंभीरतम अपराध हुए हैं। इससे महिलाएं अपने को खौफजदा महसूस करती हैं। साथ ही इसका दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। देश को महिलाओं के लिए आम तौर पर वहां असुरक्षित समझा जाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान कानून-व्यवस्था का तंत्र दुरुस्त करने के साथ-साथ समाज में जागरूकता लाना है। इसके बजाय महिलाओं को घर में सिमट जाने की सलाह देना कुछ वैसा ही है, जैसे अगर किसी के घर चोरी होती है, तो उससे पूछा जाए कि उसने धन रखा ही क्यों था। इसलिए बेहतर होगा कि नोएडा पुलिस अपना यह फरमान तुरंत वापस ले। वरना आशंका यह है कि दूसरे शहरों की पुलिस भी इससे सीख लेने लगेगी और महिला स्वतंत्रता की बलि चढ़ जाएगी। ऐसी सोच का पुरजोर विरोध किए जाने की जरूरत है।

वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआई) ने भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों की व्यापक समीक्षा की सिफारिश की

अमेरिका, ईयू सहित अनेक देश भारतीय योजनाओं को सब्सिडी के रूप में घोषित कर, प्रतिपूरक शुल्क लगाकर निर्यात्तकों को दंडित करने को रेखांकित करना जरूरी - वैश्विक स्तर पर आज दुनियां में कई देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्साहित हैं और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफडीए) करने के लिए बातचीत कर रहे हैं जिसमें ब्रिटेन के साथ करीब 12दौर की बैठके हो चुकी है। भारत अपने मिशन आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो स्वाभाविक ही है के घरेलू खपत के अलावा दुनियां के अनेक देशों में अपना माल बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा माहौल के बीच स्थान बनाना जरूरी है, जिसके लिए अनेक निर्यात स्कीम छूट सहित अनेक रणनीतिक पैसेज तैयार करने होंगे, इसके संबंध में वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल ने अनेक देशों के साथ जारी मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करनेका प्रस्ताव किया है और व्यापक समीक्षा की सिफारिश की है, क्योंकि भारत अपनी अनेक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक स्कीम्स योजनाएं चलता है, परंतु अमेरिका ईयू सहित अनेक देश इसे सब्सिडी के रूप में घोषित कर प्रतिपूरक शुल्क लगा देते हैं जो हमारे निर्यातकों को दंडित करने जैसा है। जीटीआरआई ने विशेष रूप से सिंगापुर और थाईलैंड के साथ एफडीए समझौता का मूल्यांकन करने की सिफारिश की है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, जीटीआरआई द्वारा सिंगापुर व थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर विशेष गौर करने की सिफारिश को रेखांकित करना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम वैश्विक अनुसंधान पल द्वारा 26 नवंबर 2023 को दी गई सिफारिश की करें तो, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका जैसे भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों सहित कई देश भारतीय योजनाओं को सब्सिडी के रूप में घोषित करते हैं और प्रतिपूरक शुल्क लगाकर निर्यातकों को दंडित करते हैं। वर्तमान में भारत निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। इनमें एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस), एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ईपीसीजीएस), ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम (डीडीएस), निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट (आरओडीटीईपी), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (ईओयू), प्री-शिपमेंट एंड पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट बैंक और इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम (आईईएस) शामिल हैं।इन योजनाओं का मकसद वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ानाहै। जीटीआरआई के सह संस्थापक ने कहा कि यूरोपीय संघ, अमेरिका और कई अन्य ने अक्सर इन योजनाओं को सब्सिडी के रूप में देखा है और भारत द्वारा अपने निर्यातकों को प्रदान किए जाने वाले मौद्रिक लाभों को बेअसर करते हुए प्रतिपूरक शुल्क लगाए है।इन देशों का पहला तर्क यह है कि ये योजनाएं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों (एएससीएम) पर समझौते का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा, इन चुनौतियों के

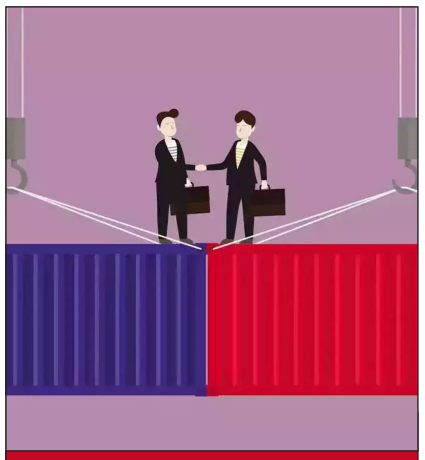

जीटीआरआई द्वारा सिंगापुर, थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर विशेष गौर करने की सिफारिश को रेखांकित करना जरूरी

चलते भारत सरकार को एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसमें निर्यात योजनाओं की संरचना में सुधार, डब्ल्यूटीओ में सक्रिय रूप से विवाद उठाना, योजनाओं की समयपूर्व निकासी का विरोध करना और सीमा शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाना शामिल हैं। कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने से सरकार को कई मौजूदा निर्यात योजनाओं की आवश्यकता में कटौती करने में मदद मिल सकती है। शोध संस्थान जीटीआरआई ने शुक्रवार को यह बात कही। उसके अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानूनों के ढांचे के भीतर इन प्रोत्साहनों के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

साथियों बात अगर हम जीटीआरआई द्वारा की गई सिफारिश में सिंगापुर थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर विशेष ध्यान देने की करें तो, सिंगापुर के साथ भारत के द्विपक्षीय एफटीए की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव दिया है, जिसमें व्यापक दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के समझौते के साथ मिलकर इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की व्यापक समीक्षा की सिफारिश की है, विशेष रूप से सिंगापुर और थाईलैंड के साथ समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया है। जीटीआरआई का सुझाव है कि यह मूल्यांकन व्यापक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ(आसियान) ब्लॉक के साथ मिलकर किया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलता की परस्पर जुड़ी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। भारत का सिंगापुर के साथ एक अलग एफटीए है जिसमें उत्पादों की उत्पत्ति के नियमों में अधिक ढील दी गई है। दोनों एफटीए का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। भारत का थाईलैंड के साथ एक अलग एफटीए है जिसे अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस) कहा जाता है, जिसमें भारत आसियान एफटीए की तुलना में मूल नियमों में छूट दी गई है। ईएचएस के जरिए पर्याप्त आयात हो सकता है। दोनों एफटीए का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है।भारत का 2010 से 10 देशों के आसियान गुट के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है, जिसमें सिंगापुर भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत ने 2005 में सिंगापुर के साथ एक अलग व्यापक एफटीए लागू किया। 2006 में अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस) के तहत थाईलैंड के साथ एक सीमित एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुझाव है कि आसियान में सिंगापुर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए,दोनों समझौतों की सामूहिक रूप से जांच की जाए। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत के अलग-अलग एफटीए की विशिष्ट विशेषताएं हैं। सुझाव यह है कि शर्तों की बारीकियों को पहचानते हुए, इन दोनों एफटीए का एक साथ विश्लेषण किया जाए। भारत और आसियान पहले ही अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका लक्ष्य 2025 तक पुनर्मूल्यांकन समाप्त करना है।आसियान ब्लॉक में ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। विशेष रूप से, पांच देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम-आसियान के साथ भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिनका निर्यात 92.7 प्रतिशत और आयात 97.4 प्रतिशत है। ये सुझाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत और आसियान देश अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। 2025 तक इस अभ्यास को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।वित्त वर्ष 2008-09 में आसियान को भारत का निर्यात 19.1 अरब अमेरिकी डॉलर था और 2022-23 में यह बढ़कर 44 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी ओर, 10 देशों के समूह से आयात पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 87.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2008-09 में 26.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत और आसियान व्यापारिक संबंधों में बदलती गतिशीलता और समायोजन की आवश्यकता को पहचानते हुए 2025 तक अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं। इस समीक्षा में सभी आसियान सदस्य देश शामिल हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पर्यावरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआई) ने भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों की व्यापक समीक्षा की सिफारिश की जीटीआरआई द्वारा सिंगापुर, थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर विशेष गौर करने की सिफारिश को रेखांकित करना जरूरी।अमेरिका, ईयू सहित अनेक देश भारतीय योजनाओं को सब्सिडी के रूप में घोषित कर, प्रतिपूरक शुल्क लगाकर निर्यात्तकों को दंडित करने को रेखांकित करना जरूरी है

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक-**दिलशाद एस खान** द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व),मुंबई-68 से मुद्रित व मुंबई हलचल,साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी-2-301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर, एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, फोन:**9619102478 /9821238815**
email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: **दिलशाद एस खान,** समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

खंडनी विरोधी दस्ते द्वारा दो पिस्टल और सात जिंदा कारतूस समेत...

नकली नोट का झांसा देखकर धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुंबई हलचल/अब्दुस समद खान ठाणे। नकली नोट का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश खंडनी विरोधी दस्ते द्वारा किया गया इस मामले में ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्राइम के उपायुक्त शिवराज पाटिल द्वारा 28 नवंबर मंगलवार दोपहर 12:00 बजे ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि खंडनी विरोधी दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागडे को गुप्त सूचना मिली कि सुरेंद्र पाटिल रहवासी डोंबिवली द्वारा पूर्व मानपाडा परिसर में बिना लाइसेंस के पिस्तौल लेकर आ रहा है जानकारी मिलती ही 25 नवंबर शनिवार को पुलिस ने जाल बिछाकर मानपाडा पुलिस स्टेशन की हद में सुरेंद्र पाटिल की मर्सिडीज गाड़ी का घेराव किया गया और गाड़ी की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी में से दो पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद किया गया जोकि बिना लाइसेंस के थे सुरेंद्र पाटिल के विरुद्ध में सहायक पुलिस उप निरीक्षक बाबर की शिकायत पर 26 नवंबर रविवार को मानपाडा पुलिस स्टेशन में गुः रजिः नंः973/2023 आर्म्स एक्ट की धारा 3,25 के

तहत मामला दर्ज किया गया और दो पिस्टल और सात जिंदा कारतूस मर्सिडीज गाड़ी को जप्त कर लिया गया उसके बाद अवैध तरीके से रखी दो पिस्टल के संबंध में की गई पूछताछ की बाद बड़े खुलासा सामने आए सुरेंद्र पाटिल ने बताया कि कुछ लोग नकली नोट बनाकर मुझे देने वाले थे जिसके लिए 40 लाख के असली नोट देकर एक करोड़ 60 लाख रुपए के नकली नोट देने का सौदा होना था यह सौदेबाजी के लिए सुरेंद्र पाटिल ने अपने पास बिना लाइसेंस के दो पिस्टल रखे थे तभी नकली नोट बनाकर देने वाले गिरोह के पांच साथी उधर आए और अपने आप को पुलिस बताकर रेड पड़ी है इस तरह का झांसा देकर उसके पास से 40 लाख रुपए की नकद रकम लेकर फरार हो गए पुलिस द्वारा छानबीन करने के बाद यह अपराध को उजागर किया गया और 26 नवंबर रविवार को सुरेंद्र पाटिल की शिकायत पर मानपाडा पुलिस स्टेशन ठाणे में गुः रजिः नंः 974/2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 420,406,170,34 के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी की सरगर्मी से की गई तलाश के बाद चार आरोपियों को भिवंडी परिसर से गिरफ्तार किया गया चार आरोपियों के पास से 14,35,000/-रुपए की नकद रकम बरामद की गई आरोपी के नाम स्वप्निल दशरथ जाधव वर्ष 26 रहवासी आनगांव तालुका भिवंडी, आदेश मोतीराम भोईर वर्ष 35 रहवासी महापौली तालुका भिवंडी, सचिन बबन जाधव वर्ष 35 रहवासी वाड़ा जिला पालघर, अक्षय तुकाराम गायकवाड वर्ष 30 रहवासी आनगांव तालुका भिवंडी आगे इस पूरे मामले की छानबीन सहायक पुलिस निरीक्षक श्री कृष्णा गौरे द्वारा की जा रही है।

महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से भारी नुकसान और मुख्यमंत्री तेलंगाना में चुनाव प्रचार में मगन

उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर तीखा प्रहार

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे ने बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र में किसानों को हुए नुकसान के बीच विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना के दौरे को लेकर मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। ठाकरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए और किसानों को जल्द से जल्द सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बेमौसम बारिश के कारण छह लोगों की जान चली गई है, जबकि 100 मवेशी भी मारे गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र

में अंगूर और प्याज की खेती करने वाले किसान भी बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया था तो राज्य मंत्रिमंडल ने क्या किया? ठाकरे ने कहा कि उन्हें मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पिछले तीन-चार दिन से बेमौसम बारिश के कारण मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में करीब एक लाख हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं है क्योंकि सभी लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अब सरकार बदलने का समय आ गया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने दावा किया, जो व्यक्ति अपने घर (राज्य) की चिंता नहीं करता और दूसरे राज्य में जाकर दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करता है वह सरकार चलाने के लायक नहीं है और उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिंदे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए मंगलवार को तेलंगाना के दौरे पर रहे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में सहयोगी हैं। ठाकरे ने कहा, जो मुख्यमंत्री अपना घर नहीं संभाल सकता और दूसरों के घर में ताक-झांक कर रहा है, वह राज्य के साथ न्याय नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और अजित पवार भी कार्रवाई करते नहीं दिख रहे हैं।

(पृष्ठ 1 का समाचार)

मुंबई में मराठी साइन बोर्ड को लेकर सख्त हुई बीएमसी

बीते शनिवार को यह अवधि समाप्त हो गई। कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बीएमसी प्रशासन सख्त हो गया है। बीएमसी प्रशासन की ओर से शनिवार को ही हिदायत दी गई थी कि मराठी में साइन बोर्ड लगाओ नहीं तो मंगलवार से कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका पर 25 सितंबर 2023 को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने दो महीने में मराठी में साइन बोर्ड लगाने का समय दिया था। पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र में रहते हुए विक्रेताओं को मराठी साइन बोर्ड के फायदे को समझना चाहिए। राज्य सरकार और बीएमसी के फैसले को खुदरा विक्रेताओं के फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चुनौती दी थी।

सोशल मीडिया से मिली जानकारी जनहित याचिका की दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकतीः बॉम्बे हाईकोर्ट

अजित के वकील मनींद्र पांडेय ने दावा किया कि इस तरह के असुरक्षित जलप्रपातों और जल निकायों में हर साल करीब डेढ़ से दो हजार लोगों की मौत होती है। इस पर पीठ ने यह जानना चाहा कि याचिकाकर्ता को मौत से संबंधित यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई। पांडेय ने अदालत को बताया कि उन्होंने यह जानकारी अखबारों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये हासिल की है। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि याचिका सतही है और इसमें बहुत सी चीजों का ब्योरा नहीं दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, सोशल मीडिया से एकत्र जानकारी एक जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने कहा, कोई पिकनिक के लिए गया और दुर्घटनावश डूब गया तो क्या इसके लिए जनहित याचिका दायर करेंगे? कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण डूब गया, तो यहां अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 12 (समानता और जीवन का अधिकार) का किस तरह उल्लंघन हुआ है।

चाचा भतीजा विवादः एनसीपी हमारी है...

दरअसल, विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की तरफ से शरद पवार ग्रुप और अजित पवार ग्रुप को नोटिस दी गई थी। नोटिस में दोनों ही पक्षों को एनसीपी की दावेदारी को लेकर जवाब दाखिल करना था। सूत्रों वे मुताबिक, शरद पवार ग्रुप की तरफ से महज 10 पेज का जवाब दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने भी एनसीपी पर अपना दावा ठोका और 40 विधायकों को अपात्र करने की मांग की। उधर, अजित पवार ग्रुप ने दावा किया कि एनसीपी में कोई टूट नहीं है। एनसीपी हमारी है। एनसीपी के संगठन से लेकर अधिकांश चुने हुए जन प्रतिनिधि सब उनके साथ हैं इसलिए एनसीपी उनकी है। बता दें कि अजित पवार ग्रुप ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 में से 42 विधायकों, नौ में से छह विधानपरिषद सदस्यों, लोकसभा एवं राज्यसभा के एक-एक सदस्य और नागालैंड से सभी सात विधायकों का समर्थन है। बता दें कि अजित पवार गुट ने 30 जून को एनसीपी के नाम, निशान और नियंत्रण को लेकर चुनाव आयोग को सूचित किया था। चुनाव आयोग दी गई जानकारी में ये बताया कि एनसीपी का अध्यक्ष अब बदल दिया गया है और अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, 2 जुलाई को अजित पवार अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत और गरमा गई। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया था। अजित पवार गुट के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी।

मध्य रेल आरपीएफ ने बचाई गई 66 जिंदगियां

अधिकांश मामलों में सतर्क आरपीएफ ने उन यात्रियों की जान बचाई है, जो कभी-कभी लापरवाही बरतते हैं और चलती ट्रेनों में चढ़ते या उतरते समय खतरे का सामना करते हैं। कई बार विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या का प्रयास करते समय लोगों की जान बचाई गई है। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के मुख्य कर्तव्य के अलावा, ऑपरेशन अमानत के तहत आरपीएफ ने अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर जरूरतमंद यात्रियों की मदद की है और उनका खोया हुआ या छूटा हुआ सामान, जैसे कि मोबाइल, फोन, लैपटॉप, यात्रियों के आभूषण, नकदी आदि वापस लाए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक ऑपरेशन अमानत के तहत आरपीएफ ने 857 यात्रियों का करीब 2.77 करोड़ मूल्य का सामान बरामद किया गया है। इन सामान पुनर्प्राप्ति मामलों में बैग, मोबाइल, फोन, पर्स, लैपटॉप और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। रेलवे सुरक्षा बल के इन जवानों को विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे यात्रियों और रेलवे संपत्तियों के खिलाफ अपराध, चरमपंथी हिंसा, ट्रेन की आवाजाही में बाधा आदि शामिल हैं।

सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम सख्त होने से बढ़ी मुश्किलें

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए एक अहम देश सऊदी अरब ने विदेशी घरेलू कामगारों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। सऊदी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट 'सऊदी गैजेट' के अनुसार, सरकार ने विदेशी घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले वीजा नियम को सख्त बनाने की कोशिश की है। वर्तमान में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के युवराज तथा सऊदी अरब के प्रथम उप प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे कम उम्र के रक्षामंत्री है। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों के तहत सऊदी अरब के अविवाहित पुरुषों या महिलाओं के लिए घरेलू काम के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब कोई भी अविवाहित सऊदी नागरिक 24 साल का होने के बाद ही घरेलू कामकाज के लिए किसी विदेशी नागरिक को काम पर रख सकता है। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही उस विदेशी कामगार के लिए वीजा जारी किया जाएगा।

सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार अब कोई भी अविवाहित सऊदी नागरिक 24 साल का होने के बाद ही घरेलू कामकाज के लिए किसी विदेशी नागरिक को काम पर रख सकता है।

शर्तों के पूरा होने के बाद ही उस विदेशी कामगार के लिए वीजा जारी किया जाएगा

बड़ी संख्या में भारतीय जाते हैं सऊदी

सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय काम करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। अब भारतीय समेत विदेशी कामगार सऊदी अरब में 24 साल से कम उम्र वाले अविवाहित नागरिकों के घर हाउस हेल्पर का काम नहीं कर सकेंगे।

वीजा जारी करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने यह निर्णय घरेलू श्रम बाजार को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए उठाया है। सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बकायदा ग्राहकों (नियोक्ता) के लिए 'मुसानेड' प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की है। जहां, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संबंधित कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच बातचीत करने की व्यवस्था की गई है।

ऑनलाइन वेतन भुगतान होगा

मुसानेड प्लेटफॉर्म पर ही एसटीसी पे और यूआरपे के माध्यम से कामगारों को वेतन ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही घरेलू श्रम अनुबंधों के प्रमाणीकरण और विवादों के समाधान जैसी सुविधाएं भी हैं। यानी यह प्लेटफॉर्म सऊदी अरब में घरेलू श्रमिकों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करता है। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ नियोक्ता और श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने और दोनों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

घरेलू कामगारों की विभिन्न श्रेणियां

घरेलू कामगारों की विभिन्न श्रेणियां हैं। जिनमें नौकर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड, किसान, दर्जी, लिव-इन नर्स और ट्यूटर शामिल हैं। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय काम करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं।

मध्यप्रदेश के गौरव को दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से किया गया सम्मानित

मुंबई हलचल / संवाददाता

मुंबई। दतिया मध्यप्रदेश के गौरव तथा बॉलीवुड के प्रसिद्ध फोटोग्राफर चंद्र प्रकाश माझी को 24 नंबर को मुंबई के एक मुक्ति फाउंडेशन, चार बंगला, अधेरी, वेस्ट, मुंबई के विशाल सभागार में आयोजित अवार्ड इवेंट में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड चंद्र प्रकाश माझी को उनके बीस सालों में फोटोग्राफर के क्षेत्र मे किए गए कार्यों के लिए बॉलीवुड का सर्वोत्तम अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंद्र प्रकाश माझी को यह अवार्ड दिए जाने से उनके प्रसंको में काफी खुशी है। तथा बॉलीवुड फोटोग्राफर चंद्र प्रकाश माझी को फिल्म जगत से जुड़े सभी लोग बधाई देते देखें जा रहे हैं।

संस्था द्वारा हर घर पौधा अभियान की होगी शुरूवात

मुंबई हलचल/सुरेश कोहली

पटौदी। क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा पटौदी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जिंदल रहे। सुखदीप बतौर विशिष्ट अतिथि रहे। राजेश जिंदल ने बताया कि संस्था गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन उपलब्ध कराती है। बताया जा रहा है कि संस्था द्वारा जल्द टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी। जानकारी के अनुसार एक कार्यक्रम के तहत हर घर पौधा अभियान का रूप दिया गया है जिससे एक कॉल के माध्यम से आपके घर पौधा पहुंच जाएगा। जिंदल ने बताया कि आने वाले समय में संस्था द्वारा मुफ्त मार्शल आर्ट की कोचिंग देने का प्रावधान भी किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रभारी मा. सुरेंद्र चौहान ने बताया कि संस्था का मुख्य मकसद गरीब व असहाय कीं मदद करना व देश से भ्रस्टाचार कीं जड़ को कमजोर करना है। इस अवसर पर रविन्द्र कुमार स्वामी, करण सिंह, सुरेंद्र वर्मा, विकासदीप विक्की, प्रमिला देवी, अशोक कुमार, अमित कुमार, मनोज मोरवाल, कृष्ण सोनी आदि मौजूद रहे।

रोड न्यू प्वाइंट मालिक एंड संस का उद्घाटन समारोह मौलाना शकील अहमद कासमी साहब की दुआओं के साथ आयोजित किया गया

मुंबई हलचल/सालीम आजाद

मधुबनी। रोड न्यू प्वाइंट मलिक एंड संस का उद्घाटन कार्यक्रम क्यूटी ब्लॉक दर्मा चौक बरारी पेट्रोल पंप के पास आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसमें जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं। मौलाना शकील अहमद कासमी साहब ने दुआ के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया विशिष्ट अतिथि के रूप में जनता दल के राज्यसभा सदस्य डॉ फैयाज अहमद साहब उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल के महा सचिव डॉ. आसिफ साहब भी उपस्थित थे और क्यूटी विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ. फराज फातमी साहब और क्षेत्र की अन्य प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियाँ भी उपस्थित थीं। रूहुल्लाह साजिद नदवी साहब और वलीउल्लाह साहब दोनों भाइयों ने सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत किया और सभी लोगों को धन्यवाद दिया। बिस्फी प्रखंड के लोगों के लिए यहां से दरभंगा और मधुबनी दोनों जगहों पर उचित मूल्य पर गिट्टी, बालू, सीमेंट की थोक आपूर्ति की जाएगी और लोगों को सामान कम कीमत पर और अच्छी मात्रा में मिलेगा। रोड नियु प्वाइंट सन्स जरूर जाएं।

मुंबई में अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रही महिला ने की आत्महत्या

मुंबई। भारतीय नौसेना में अग्निवीर का प्रशिक्षण ले रही 20 वर्षीय महिला ने मुंबई में आईएनएस हमला में अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटककर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि केरल की रहने वाली यह महिला पश्चिमी उपनगर मलाड में मालवानी इलाके में आईएनएस हमला में प्रशिक्षण ले रही थी। उन्होंने बताया कि महिला ने सोमवार को सुबह अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटककर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और प्रतीत होता है कि महिला ने निजी कारणों से आत्महत्या की।

चाय दुकानदार पर अपराधियो ने किया फायरिंग, बाल बाल बचा

मुंबई हलचल/जकी अहमद

समस्तीपुर। शहर के मोहनपुर रोड में आदर्श नगर मोड़ पर बदमाशों ने एक चाय दुकान पर तीन राउंड फायरिंग की। मंगलवार की दोपहर बाईक सवार बदमाशों ने भीड़भाड़ के बीच घटना को अंजाम दिया, हालांकि इस घटना में चाय दुकानदार शंभू साह बाल बाल बच गया। इस घटना में किसी जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अचानक हुई इस गोलीबारी की घटना से अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। लोग गोली चलते देख इधर - उधर जान बचाकर भागने लगे। बताया जाता है कि बदमाशों ने एचडीएफसी के एटीएम के नीचे ठेला लगाकर चाय बेचने वाले शम्भू साह को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की थी, लेकिन संयोग से वह बाल बाल बच गया। गोलियां लगने से उसके दुकान के काउंटर के कांच एवं उसपर रखे कांच के बोईयाम चकनाचूर हो गये। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश आदर्शनगर की ओर फरार हो गये घटना की सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस छानबीन में जुट गयी है, पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा भी बरामद किया है, पीड़ित चाय दुकानदार के अनुसार एक जमीन की खरीद बिक्री को लेकर 9 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद चल रहा था। इसको लेकर ही बदमाशों ने उसपर फायरिंग की है। बहरहाल इस घटना को लेकर चाय दुकानदार शंभू साह डरे और सहमे हुए हैं।

जी20 अध्यक्षता से उत्साहित पर्यटन मंत्रालय भारत मंडपम में 30 नवंबर को करेगा आयोजन

भारत को वैश्विक एमआईसीई डेस्टीनेशन के रूप में विकसित करने के लिए बनेगा रोडमैप

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर अभूतपूर्व रुचि पैदा हुई। इसने भारत के मजबूत एमआईसीई बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। इससे उत्साहित होकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई के क्षेत्र में भारत की पहचान स्थापित करने का निर्णय लिया है। एमआईसीई से तात्पर्य एम-मीटिंग (बैठक), आई-इन्सेंटिव (प्रोत्साहन), सी-कॉन्फ्रेंस (सम्मेलन) और ई-एक्जीबिशन (प्रदर्शनियों) से है।

खास बातें

- भारतीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दुनिया ने देखी
- एमआईसीई क्षेत्र में दुनिया को करेंगे आकर्षित
- एमआईसीई ईकोसिस्टम विकसित करेंगे
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का करेंगे उपयोग

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर अभूतपूर्व रुचि पैदा हुई। इससे उत्साहित होकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई के क्षेत्र में भारत की पहचान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

एमआईसीई को बढ़ावा देना उद्देश्य

पर्यटन मंत्रालय भारत को एक प्रमुख वैश्विक एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भारत मंडपम, नई दिल्ली में 30 नवंबर को उद्योग गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। बैठक में भारत को एक प्रमुख एमआईसीई डेस्टीनेशन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख पहलों के बारे में विस्तार से बताएगा। एमआईसीई उद्योग के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप है, जो भारत को बड़े सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

एमआईसीई के बारे में मांगेगा सुझाव

मंत्रालय ने शहरों को एमआईसीई गंतव्य के रूप में सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए शहर स्तरीय एमआईसीई प्रमोशन ब्यूरो स्थापित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है। मंत्रालय सिटी एमआईसीई ब्यूरो मॉडल के बारे में उद्योग से जुड़ी हस्तियों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगेगा जो एमआईसीई गंतव्य पर एक पूर्ण एमआईसीई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ काम करेगा और शहर में कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों के आयोजन के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप पर विचार-विमर्श

पर्यटन मंत्रालय इस गोलमेज बैठक में भारत को एक प्रमुख एमआईसीई गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख पहलों के बारे में विस्तार से बताएगा। इन प्रयासों के केंद्र में एमआईसीई उद्योग के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप है, जो भारत को बड़े सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। पर्यटन मंत्रालय एमआईसीई के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए दुनिया को आकर्षित करेगा।

जी20 अध्यक्षता से अभूतपूर्व रुचि पैदा हुई

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर अभूतपूर्व रुचि पैदा हुई। इसने भारत के मजबूत एमआईसीई बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है।

'मीट इन इंडिया' लॉन्च

भारत को एमआईसीई गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक समर्पित ब्रांड 'मीट इन इंडिया' लॉन्च किया है। राज्यों और उद्योग जगत के साथ साझेदारी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं।

पाक कलाकारों पर बैन लगाने की याचिका रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'छोटी सोच न रखें'

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाकिस्तान के कलाकारों को प्रतिबंधित करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत में दायर याचिका में अपील की गई थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में प्रदर्शन या काम करने की अनुमति न दी जाए। कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए अदालत ने फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। यह समय सीमा अब (साल 2023 में) खत्म हो गई है।

सिने एक्टिविस्ट फैज अनवर कुरैशी ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुप्रीम कोट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं है। आपको भी इस अपील पर दबाव नहीं डालना चाहिए।

पाक कलाकारों पर लगाएं बैन

याचिकाकर्ता अनवर कुरैशी ने कोर्ट से अपील की थी- आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वह भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों और संघों पर किसी भी पाकिस्तानी को रोजगार देने, पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम ऑफर करने, पाकिस्तानी नागरिकों की कोई सेवा लेने या किसी भी संगठन में प्रवेश करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। जिन लोगों पर प्रतिबंध की मांग की गई है, इनमें सिने कर्मी, गायक, संगीतकार, गीतकार और तकनीशियन शामिल हैं।

देशभक्त होने के लिए दुश्मनी ठीक नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा था कि यह याचिका सुनवाई करने लायक नहीं है। लोगों को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए पड़ोसी देश के लोगों से नफरत रखना सही नहीं है। देशभक्त होने का अर्थ है कि अपने देश के लिए समर्पित रहें। देश के भीतर और सीमा पार नृत्य, कला, संगीत, संस्कृति, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का स्वागत करें।

साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया था

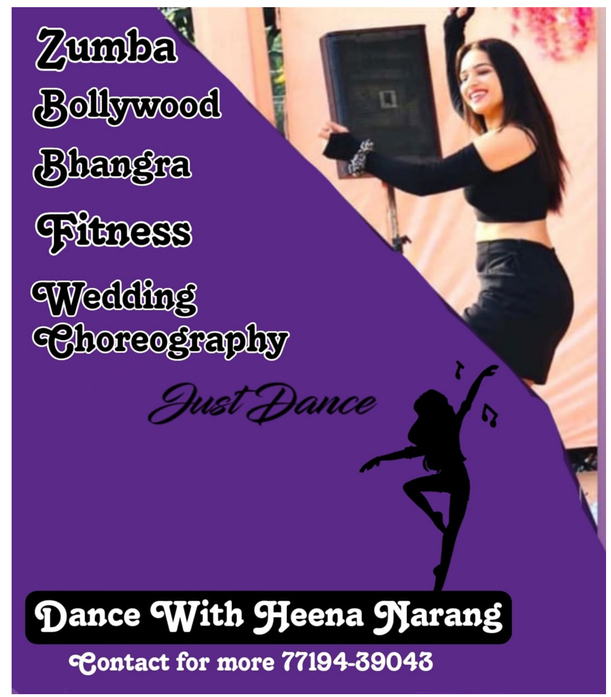

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

उत्तराखंड हलचल

17वे दिन सकुशल सिलक्यारा टनल से बाहर निकले श्रमिक

मुंबई हलचल/ वैभव पेटवाल

सिलक्यारा/उत्तरकाशी। मंगलवार को पूरे देश के लिए मंगलमयी खबर सामने आई है। डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व और रेस्क्यू टीमों के अथक परिश्रम से ऑपरेशन सिलक्यारा फतह कर लिया गया है। सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिक 17वें दिन सकुशल बाहर आ गए हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में निमार्णाधीन सुरंग में 12 नवंबर को भूधंसाव होने से 41 श्रमिक सुरंग में ही फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। देहरादून से पहुंचे एसडीआरएफ के जवान स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के साथ तत्काल रेस्क्यू में जुट गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके का जायजा लेने पहुंचे। सीएम के दौरे के साथ ही रेस्क्यू अभियान जोर पकड़ गया। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गईं।

सुरंग में मलबा हटाने के लिए सबसे पहले जेसीबी लगाई गई, लेकिन ऊपर से मलबा गिरने पर सफलता नहीं मिल पाई तो देहरादून से ऑगर मशीन मंगाकर सुरंग में ड्रिलिंग शुरू की गई।

ऑगर मशीन जवाब दे गई। फिर दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन मौके पर पहुंचाई गई। इसके लिए वायुसेना के हरक्यूलिस विमानों की मदद ली गई। इन विमानों ने मशीन के पुर्जों को चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर पहुंचाया और यहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिलक्यारा पहुंचाया गया।

सुरंग में लगभग 50 मीटर ड्रिलिंग के बाद सरिया सामने आने के कारण इस मशीन में भी खराबी आ गई। फिर हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया। कटर से ऑगर को काटने के बाद 16वें दिन मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई और आज 17वें दिन जिंदगी का पाइप श्रमिकों तक पहुंचा दिया गया। यही नहीं सरकार तीन अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही थी। इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी 50 मीटर तक पहुंच चुका था।

रेस्क्यू टीमों को सैल्यूट

राज्य और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां, अधिकारी और कर्मचारी आज 17वें दिन तक पूरी तन्मयता और मनोयोग से रेस्क्यू में जुटी रही। मुख्यमंत्री धामी निरंतर स्थलीय निरीक्षण करने साथ ही रेस्क्यू टीमों की हौसला-अफजाई करते रहे। इसी का फल रहा है कि आज यह मिशन सफल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना, वायुसेना समेत तमाम संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।

सुरंग में फंसे श्रमिकों को एक-एक लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार, अस्पताल में ले पूरा इलाज, घर जाने तक की पूरी मदद भी मिलेगी - धामी

मुंबई हलचल/ वैभव पेटवाल

सिलक्यारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों सभी श्रमिकों को सरकार एक एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में इलाज और घर जाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी।

सिलक्यारा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज पर होने वाला खर्चा सरकार उठाएगी।इनके अलावा परिजनों और श्रमिकों के खाने, रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के

स्वस्थ होने पर सरकार की तरफ से एक एक लाख रुपये के चेक बतौर आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा घर जाने तक का पूरा खर्चा भी सरकार वाहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा जल्द बनेगा भगवान बौखनाग का भव्य मंदिर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा बौखनाग और देवभूमि के देवी-देवताओं की कृपा से ऑपरेशन सफल हुआ है। कहा कि बौखनाग देवता का सिलक्यारा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल आये हैं। कहा कि ग्रामीणों ने बाबा बौखनाग के मंदिर बनाने की मांग उठाई है। इस मांग को सरकार पूरा करेगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि, जल्द मंदिर निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी जाए।

मुख्यमंत्री ने किया छठवें वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का शुभारम्भ

मुंबई हलचल/ वैभव पेटवाल

देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्लेमेंट टाउन देहरादून स्थित, एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। 28 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकि सत्र आयोजित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में ह्यराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थानह्ल खोलने के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा। राज्य में इस संस्थान की खोलने के लिए केन्द्र सरकार की जो भी अपेक्षा होगी, वह राज्य राज्य सरकार द्वारा पूरी की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग और महिलाओं के लिए राज्य में आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष प्राविधान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्व विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम शामिल किये जायेंगे और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 08-09 दिसम्बर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश-विदेश के औद्योगिक समूहों, निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को गति देने के लिए प्रतिभाग किया जायेगा। इस सम्मेलन से ठीक पहले आयोजित आपदा प्रबन्धन के वैश्विक सम्मेलन से उत्तराखण्ड में ह्यसुरक्षित निवेश-सुदृढ़ उत्तराखण्डह्ल का संदेश देश-विदेश में प्रसारित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन के माध्यम से समेकित विकास लक्ष्यों के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन और जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने में सहायता मिलेगी।

चीन में तेजी से फैलती नई बीमारी ने बढ़ाई उत्तराखंड में टेंशन

मुंबई हलचल/ संवाददाता

देहरादून। चीन में बच्चों में फैल रहे निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने गाइडलाइन जारी की है। बच्चों में निमोनिया, इन्फ्लूएंजा फ्लू के लक्षणों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी माइक्रो प्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लूएंजा फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी देश के सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशा-निर्देश दिए हैं। राज्य में सर्विलांस बढ़ाया जाए। उत्तराखंड में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों को भी अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड, वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रखी जाए। चिकित्सकों के साथ नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जाए। नाक और गले की जांच के सैंपल को नजदीकी मेडिकल कालेज में भेजा जाए। समुदाय स्तर पर यदि कहीं भी परेशानी सामने आती हैं, तो तत्काल जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तत्काल नियंत्रण, रोकथाम की कार्यवाही की जाए। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए। छींकते, खांसते समय नाक और मुंह को ढकने को मास्क, रुमाल का इस्तेमाल किया जाए। साबुन-पानी से हाथों को धोकर साफ रखा जाए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज किया जाए। चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाएं ली जाएं। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय भी अलर्ट मोड पर आ गया है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

आध्यात्मिक गुरु ओशो की भूमिका निभाना चाहूंगाः इफ्फी में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। आनंद सुरपुर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म रौतू की बेली का आज गोवा में 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भव्य प्रीमियर हुआ। यह फिल्म उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में स्थित रौतू की बेली नाम के एक रमणीय शहर पर आधारित है, जो दर्शकों को उस शहर के एक स्कूल के वार्डन के मृत पाए जाने के बाद इंस्पेक्टर नेगी के साथ एक खोजी यात्रा पर ले जाती है। पीआईबी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए रौतू की बेली के मुख्य अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि देश भर के स्थानीय पुटवाली प्रामाणिक कहानियों को दशार्ने वाली फिल्मों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी।

जितना अधिक स्थानीय पुट, उतना अधिक वैश्विक। किसी फिल्म में अपनी भूमिका चुनने से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं खुद को सिर्फ एक खास तरह की भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहता और मैं भूमिकाओं की विविधता को प्राथमिकता दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वह किसी भी भूमिका को निभाते समय उस पात्र की जिंदगी को इस हद तक जीने की कोशिश करते हैं कि उस पात्र की जिंदगी और उनकी खुद की जिंदगी एक में मिल जाए।

जब अभिनेता सिद्दीकी से उस भूमिका के बारे में पूछा गया जिसे वह भविष्य में निभाने के लिए उत्सुक होंगे, तो उन्होंने कहा, यदि अवसर मिला तो मैं आध्यात्मिक गुरु ओशो की भूमिका निभाना चाहूंगा। फिल्म निर्माण के लिए मिलने वाली प्रेरणा से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, निर्देशक, आनंद सुरपुर ने कहा कि कहानी कहने का जुनून और अनूठे विचार मेरी प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। जी स्टूडियोज के सीईओ और फिल्म रौतू की बेली के पटकथा लेखक शारिक पटेल ने कहा कि यह फिल्म अपने पात्रों के निरूपण की दृष्टि से शैली से परे जाने वाली एक फिल्म है और इसमें रहस्यात्मक हत्या की एक अनूठी कहानी है।इस फिल्म की रिलीज के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि यह फिल्म 2024 की शुरूआत में जी 5 पर उपलब्ध होगी।

मेरी फिल्मों में भारतीय महिलाओं का सशक्त चित्रण : गोवा में आईएफएफआई के 54वें संस्करण के दौरान रानी मुखर्जी

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में आज हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ 'दमदार प्रस्तुति देना' विषय पर दिलचस्प इन कन्वर्सेशन सत्र आयोजित किया गया। गैलाट्टा प्लस के प्रधान संपादक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म समीक्षक बरद्वाज रंगन द्वारा संचालित इस सहज चर्चा में रानी मुखर्जी के जीवन और शानदार करियर पर प्रकाश डाला गया।अपनी सिनेमाई यात्रा पर मंथन करते हुए रानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा भारतीय महिलाओं को सशक्त किरदार के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भारत के बाहर, फिल्मों और उनके किरदारों को हमारी भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने वाली खिड़की के रूप में देखा जाता है। कला के लिए प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर देते हुए इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने कहा, हमेशा मजबूत फिल्मों और भूमिकाओं के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कभी-कभार आपको उसी समय दर्शकों की सराहना नहीं मिल पाए, लेकिन सिनेमा के इतिहास में, ऐसी फिल्में और किरदार अपनी जगह बना लेंगे। रानी मुखर्जी ने अभिनेता के बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के महत्व को भी रेखांकित किया। इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, यदि कोई अभिनेता बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, तो वह जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित कर सकता है। मैं अपने किरदारों को जितना अधिक विविधतापूर्ण बना सकती हूं, यह दर्शकों और मेरे लिए उतना ही दिलचस्प होगा। किरदारों में यह विविधता भी मुझे प्रेरित करती है।

चरित्र चित्रण की जटिलताओं की पड़ताल करते हुए रानी ने बताया, विशेष भूमिकाएं निभाने के लिए, अक्सर अभिनेता वास्तविक जीवन के उसी तरह के लोगों से

मिलते हैं, ताकि वे उस किरदार की विशेषताओं को सही ढंग से व्यक्त कर सकें। लेकिन यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि वे किन भावनाओं से गुजर रहे हैं। किसी भी फिल्मी दृश्य के पीछे की भावनाएं ही उस दृश्य को अलग बनाती हैं। दर्शकों के दिल तक पहुंचने के लिए भावनाओं को चित्रित करना महत्वपूर्ण है।इफिल्म उद्योग में आयु के आधार पर भेदभाव के विषय पर इस प्रसिद्ध अभिनेत्री ने कहा कि अभिनेताओं को अपनी उम्र को स्वीकार करते हुए अपनी उम्र के अनुरूप भूमिकाएं करनी होंगी,ताकि दर्शक उन्हें उस भूमिका में स्वीकार कर सकें। उन्होंने कहा कि दर्शकों ने उन्हें फिल्म उद्योग में आयु के आधार पर भेदभाव और अन्य बाधाओं को तोड़ने में मदद की। निजी विचार साझा करते हुए रानी ने कहा, मैं आयु को ज्यादा महत्व नहीं देती और अपने किरदारों के साथ न्याय करने की कोशिश करती हूं। यदि आप अपने द्वारा निभाए जा रहे किरदार की तरह ही दिखते हैं, तो लोगों को उस किरदार के प्रति भरोसा कराने की आधी लड़ाई तो आप उसी समय ही जीत लेते हैं।

अपनी यात्रा पर संतोष व्यक्त करते हुए इस विख्यात अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें अपने सिनेमाई जीवन में किसी भी किरदार को निभाने का कभी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि मैं डेट क्लैश के कारण आमिर खान द्वारा निर्मित उनकी प्रथम फिल्म 'लगान' का हिस्सा नहीं बन सकी। रानी मुखर्जी ने फिल्म कुछ कुछ होता है की 'टीना मल्होत्रा' से लेकर कभी अलविदा ना कहना की 'माया तलवार' और मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की 'देबिका चटर्जी' तक, अपने सैकड़ों खूबसूरत किरदारों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। अपने निभाए सबसे पसंदीदा किरदार के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि फिल्म 'ब्लैक' का किरदार उनके दिल के सबसे करीब है। उन्होंने कहा कि इस किरदार ने उन्हें बदलकर रख दिया और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। उन्होंने कहा, ब्लैक में 'मिशेल मैकनेली' के किरदार ने मुझे प्रेरणा देने के साथ ही साथ चुनौती भी दी। 'मेहंदी' के किरदार ने भी मुझे सशक्त बनाया।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

तापसी का रिएक्शन

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बॉलिवुड ऐक्ट्रेस तापसी पन्नू और सिंगर सोना महापात्रा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर हैरत जाहिर की है। हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि पत्नी के साथ उसकी बिना मर्जी के जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं माना जा सकता है। एक 37 साल की महिला ने अपने पति पर जबरन सेक्स करने, मारपीट करने और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में यह टिप्पणी की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वह हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं। कोर्ट के इस फैसले पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तापसी ने इस मामले में एक न्यूज क्लिप को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, बस अब यही सुनना बाकी था। कोर्ट की इस टिप्पणी पर मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने भी नाराजगी जाहिर की है। सोना ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'इसे पढ़कर मुझे जो घटियापन महसूस हो रहा है उसे मैं यहां लिख नहीं सकती।' तापसी पन्नू के अलावा सिंगर सोना मोहापात्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया– इस भारत को पढ़कर मुझे जो बीमारी महसूस हो रही है। वह किसी भी चीज से परे है जिसके बारे में मैं लिख सकती हूं।

डिब्बाबंद हुई विक्की कौशल और सारा अली खान की 'अश्वत्थामा'

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल बीते कई दिनों से अपनी फिल्म 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में विक्की के साथ सारा अली खान नजर आने वाली थीं। वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनने वाली 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' डिब्बा बंद हो चुकी है। इस फिल्म के बंद होने के कारण मेकर्स को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अश्वत्थामा के मेकर्स को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खबरों के अनुसार फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला इस प्रोजेक्ट पर लगभग 30 करोड़ खर्च कर चुके हैं और जब उन्होंने फिल्म पूरा बजट जोड़ा तो उन्हें लगा कि यह काफी महंगी फिल्म हो जाएगी। कोविड की वजह से पहले ही फिल्में सिनेमाघरों में बिजनेस नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि रॉनी स्क्रूवाला रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं और वो 30 करोड़ का नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। वह फिल्म का प्रोडक्शन शुरू करके और रुपए का नुकसान हीं उठाना चाहते हैं। इस फिल्म के बजट को लेकर खबर आई थी कि इसका बजट करीब 300 करोड़ रुपए होने वाला था।

'अय्यप्पनम कोशियुम' के हिन्दी रीमेक से बाहर हुए अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की जोड़ी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है। बीते दिनों खबर आई थी कि अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम साउथ की हिट फिल्म 'अय्यप्पनम कोशियुम' के हिन्दी रीमेक में साथ नजर आने वाले हैं। गहालांकि अब फैंस के लिए थोड़ी निराश करने वाली खबर सामने आई है। ताजा खबरों के अनुसार अभिषेक बच्चन इस फिल्म से बाहर हो गए हैं। फिल्म की शूटिंग इसी नवंबर में शुरू होने वाली थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन जॉन के साथ फिल्म करने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है यहां कुछ भी पॉसिबल है। फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम की टीम अभिषेक के रिप्लेसमेंट की तलाश रही है। मेकर्स का मानना है कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक ही शूटिंग शुरू करेंगे।

अपने आप को बॉलीवुड की दुल्हन मानने लगी हैं कृति खरबंदा

यूं तो शादी में होने वाली गड़बड़ियों पर कई फिल्में बनी है। कभी लड़के की तरफ से गड़बड़ होती है तो कभी लड़की की तरफ से। लेकिन एक ही लड़की से दोबारा शादी करने वाला मौका ऐसा फिल्मों में जरा कम ही दिखता है और शायद इसीलिए इस फिल्म का नाम 14 फेरे रखा गया है। फिल्म '14 फेरे' की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वेबदुनिया से बात करते हुए कृति खरबंदा कहती हैं, मैं तो अपने आप को बॉलीवुड की दुल्हन मानने लग गई हूं। मैंने एक या दो बार नहीं 8 बार दुल्हन का रोल निभाया हुआ है। दुल्हन के कपड़े, दुल्हन की ज्वेलरी पहनी हैं। मुझे लगता है कि मैं जब भी फिल्म के लिए शादी का रोल निभाती हूं या जिस फिल्म में मेरी शादी होती है, वह बड़ी लकी हो जाती है। उन्होंने कहा, मेरे लिए फिल्म 14 फेरे सिर्फ शादी के बारे में नहीं है या सिर्फ शादी हो जाने के लिए नहीं बनाई है। यह एक लव स्टोरी है। प्रेम कहानी है संजू और अदिति की। यह एक सफर है, संजू और अदिति की प्रेम कहानी को शुरूआत से लेकर शादी तक के अंजाम तक पहुंचाने का। यह आज के समय में बहुत जरूरी है। यह बहुत ही प्रासंगिक लव स्टोरी कह सकते हैं। इनके किरदार कि अगर मैं बात करूं तो आप चाहोगे कि ऐसे किरदार आपके आसपास रहते हो। आप चाहोगे कि आपके रिश्ते में ऐसी मासूमियत हो दिन भर आप लड़े– कुछ भी बात हो जाए। लेकिन अगले दिन वो कहते हैं ना रात गई बात गई वाली बात हो जाए। जितनी भी परेशानी है, जितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन हम साथ में हमेशा रहेंगे वैसे तरीके की लड़की बनी हूं।